बिहार के स्कूल में धर्म-जाति में बांट कर पढाई

फहमीना हुसैन

पटना: स्कूल, जहाँ धर्मनिर्पेक्षिता का पाठ पढ़ने वाले ही अगर धर्म, जाति के नाम पर बाटना शुरू कर दें तो देश का क्या भविष्य हो सकता है? ऐसा ही एक मामला बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हैरान करने वाला चेहरा सामने आया। जहाँ बच्चों को मिलने वाले आरक्षण का हवाला देते हुए जातीय और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है।

बिहार के वैशाली जिले के जी.ए उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालय लालगंज जहां के स्कूलों में बच्चों के लिए अलग अलग क्लासरूम दलितों, मुसलमानो, पिछडो और स्वर्णो के लिए बनाये गए है. जहाँ सेक्शन, कलासरूम से लेकर छात्रों के रजिस्टर तक जाति और धर्म के आधार पर बांटा गया। विद्यालय ने यह व्यवस्था पिछले चार सालों से लागू कर रखा है।

दरअसल बिहार के वैशाली जिला लालगंज के राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपास के इलाके का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है। इस स्कूल की बात करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय ने भी यही से अपनी स्कूली शिक्षा ली है।

दैनिक जागरण की ख़बर के अनुसार स्कूल की प्रधानाध्यापिका मीणा कुमारी का कहना है कि नौंवी कक्षा में कुल 770 छात्र-छात्राएं हैं। जिन्हें 6 अलग-अलग सेक्शनों को दो भागों में बांट गया है जिसमें 70-70 छात्रों की संख्या को वन और टू में बांटा गया है। नौवीं A-1 में केवल मुस्लिम छात्राएं और नौवीं A-2 में केवल मुस्लिम छात्र हैं। वहीं B-1 में सिर्फ अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राएं और B-2 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र शामिल हैं।

कि इस मामले में मीणा कुमारी का तर्क है कि हमने स्कूल के बच्चों की पढ़ाई में सुविधा और योजनाओं की सहूलियत के लिए ऐसा किया किया।

वही वैशाली के मेन समिति बाजार के रहने वाले 38 वर्षीय सरोज सिंह ने बताया कि मीडिया द्वारा जिस तरह से स्कूल को बदनाम किया जा रहा है वो गलत है. राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं ही ऐसी बनाई गई हैं कि बटवारा करना बिलकुल उचित है।

उन्होंने आगे कहा की अगर क्लासरूम का बटवारा जाति या धर्म के नाम पर किया जा रहा है तो इन सब की जड़ आरक्षण है, सरकार को आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए।

वहीं वैशाली जिले के महुआ के रहने वाले 31 वर्षीय अजीज अंसारी का कहना है कि ये ऐसा कोई चौकाने वाला मामला नहीं है बिहार में ऐसी व्यवस्था बहुत मामूली सी घटना है। उन्होंने बताया कि जहाँ सरकारी स्कूलों में ऐसी बटवारे की घटना नहीं वहां छात्रवितीं या पोषक राशि में जातीय और धार्मिक भेदभाव किया जाता है।

उन्होंने बताया कि मुस्लिम बच्चों को कम उपस्थिथ दिखा कर पोषक या छात्रवृति ही नहीं मिल पाती फिर मुस्लिम बच्चे-बच्चियां स्कूल नहीं जा पाते तो ऐसे में सरकार अल्पसख्यक के ड्रॉपआउट का आकड़ा पेश कर ना पढ़ने का कारण बता देती है।

इस मामले में पटना के रहने वाले 26 वर्षीय इकबाल अहमद का मानना है कि बिहार हो या कोई और राज्य जातीय धार्मिक भेद की मानसिकता को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इस तरह की घटना इस बात का सबूत है. लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट का बटवारा चाहतें हैं वैसे ही अब बच्चों को भी शिक्षा के नाम पर अपने सोच को धर्म और जाति में बाँट रहे हैं।

हालांकि इकबाल ने आगे कहा कि जो पिछड़े है उनको आगे लाने के लिए सरकार दलित, आदिवासी, या अल्पसंख्यकों को योजना का लाभ मिले इस लिए ऐसे सहूलत रखी है लेकिन कुछ लोग अपनी गलत मानसिकता की वजह से गलत तर्क देने में लगे हैं।

बीके अस्पताल: सरकारी खजाने में सेंध, अनाधिकृत धन निकासी

फ़रीदाबाद (म.मो.)। सरकारी खजाने से धन निकासी के कुछ कड़े नियम सरकार द्वारा बनाये गये हैं ताकि इस पर नियन्त्रण रखा जा सके। इसके लिये सरकार हर विभाग में एक अधिकारी विशेष को ध्यान निकासी का अधिकार बाकायदा लिखित में देती है। उस अधिकारी को ड्राइग एंड डिसबरसिंग अधिकारी कहा जाता है।

यहां पर यह अधिकार बतौर सीएमओ डा. असरुदीन के पास था। करीब 3 माह पूर्व उनकी पदोन्नति एवं तबादला हो जाने के बाद यहां पर यह अधिकार किसी को नहीं दिया गया। सीएमओ कार्यालय का कामकाज चलाने के लिए डा. वीर सिंह सहरावत को काम चलाऊ सीएमओ तो नियुक्त कर दिया गया परन्तु उन्हें धन निकासी के अधिकार नहीं दिये गये। इसके बावजूद उन्होंने चैक साइन करके बैंक से लाखों रुपए निकलवा लिये।

जानकार बताते है कि राजेश नामक एक क्लर्क ने बैंक मैनेजर से डा. असरुदीन की जगह बीर सिंह सहरावत को अधिकृत हस्ताक्षरी बनवाने का प्रयास किया था, लेकिन सरकारी लिखित आदेश के बिना बैंक मैनेजर हस्ताक्षरी बदलने से इंकार कर दिया था। इसके बावजूद उसी बैंक मैनेजर की मिलीभगत से 698000 के वे चैक पास कर दिये जिन पर डा. सहरावत के हस्ताक्षर थे।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार दलाली व रिश्वतखोरी का धंधा करने वाले फार्मासिस्ट सांगवान, जिसने तत्कालीन सीएमओ सहरावत को अपनी मुट्ठी में कर रखा था, वे राजेश क्लर्क ने यह सारा परपंच रचा। डा. सहरावत सीएमओ तो जरूर थे परन्तु उनमें अक्ल नाम की तो कोई चीज थी नहीं, जहां सांगवान कहता वहां अपनी मुहर टिका देते थे जिसके बदले लूट के माल में से कुछ टुकड़ा वह उन्हें भी दे देता था।

उक्त रकम (698000) में से 98000 रुपए सफेदी व पेंट पॉलिश के दिखाये गये हैं। जबकि न तो कोई सामान स्टोर में आया न कहीं सफेदी हुई। यह रकम ब्लड बैंक के खाते से निकाली गयी थी। तमाम धन निकासियों का मास्टर माईड तो बेशक सांगवान और असल उत्तरदायी तो डा. सहरावत ही हैं लेकिन वे लोग भी कम उत्तरदायी नहीं हैं जिन्होंने फाइलों पर दस्तखत करके लूट में से अपना-अपना हिस्सा पत्ती वसूल की है। यह पूरा विशेष विभागीय जांच का मामला है। परन्तु जहां नीचे से ऊपर तक सभी चोर हो अर्थात हर शाख पर उल्लू बैठा हो तो वहां किसी का कुछ बिगड़ता नहीं। हां, जांच के नाम पर जांच अधिकारी जरूर लूट में से अपना हिस्सा वसूल कर ले जायेगा।

इस तथ्यात्मक जानकारी से जनता को यह जरूर समझ लेना चाहिए कि शासन प्रशासन चलाने वाले सत्तारूढ़ नेताओं की औकात क्या है। जरूरतमंद मरीजों के लिए तो रैबीज के टीके व अन्य साधारण दवाइयां तक उपलब्ध नहीं होती और सरकारी लुटेरों को लूट की पूरी आजादी है। यही तो है खट्टर का भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा।

दोबारा नौकरी के लिए चक्कर लगाते डा. सहरावत

सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाते हुए डाक्टरों को 65 वर्ष की आयु तक नौकरी की छूट दी है। लेकिन 7 वर्ष तक बढ़ी इस कार्य अवधि में वे किसी प्रशासनिक पद पर तैनात नहीं हो सकते, यानी वे केवल मरीज देख कर उनका इलाज कर सकते हैं। सीएमओ के पद से रिटायर हुए डा. सहरावत अब बीके अस्पताल में आकर रोजाना गुहार लगा रहे हैं कि उनकी ज्वायनिंग की जाये। लेकिन संबंधित अधिकारी कह देते हैं कि इसके मुख्यालय (चण्डीगढ़) से आदेश आने पर ही वे उन्हें नौकरी पर रख सकते हैं। विदित है कि डा. सहरावत कोई विशेष नहीं है, वे केवल साधारण एमबीबीएस हैं, इसलिये यदि दोबारा नौकरी मिलती भी है तो किसी गांव की डिस्पेंसरी आदि में ही मिल पायेगी।

किसी से छिपा नहीं है कि बढ़िया इलाज करने वाला कोई भी डाक्टर इस तरह नौकरी की भीख नहीं मांगता, बल्कि अधिक बढ़िया डाक्टर तो लगी लगाई नौकरी छोड़कर अपना निजी क्लीनिक खोल लेते हैं केवल नालायक डाक्टर ही इस तरह नौकरी की भीख मांगते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि न तो उन्हें मरीज देखने आते न इलाज करना, ऐसे में हरामखोरी के बदले केवल सरकार ही अच्छा खासा वेतन दे सकती है।

जींद में रणदीप सूरजेवाला को उतारने का गहरा मतलब है

कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा टाइप राजनीति से मुक्ति चाहती है

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली: जींद में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैदान में उतारा है। हरियाणा की सियासत में यह सवाल जोर-शोर से पूछा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस को सुरजेवाला को इस चुनाव में उतारने की ज़रूरत क्यों पड़ी।

सीधा सवाल सीधा जवाब

इस सवाल का सीधा जवाब ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह फैसला हरियाणा की दूरगामी राजनीति को लेकर किया लगता है। यह बहुत साफ है कि भाजपा के हालात को देखते हुए कांग्रेस हरियाणा के अगले चुनाव में वापसी कर सकती है। जींद उपचुनाव के जरिए राहुल ने हरियाणा कांग्रेस को यह संकेत दिया है कि पार्टी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से छुटकारा पाना चाहती है। ऐसे में राहुल के विश्वासपात्र बन चुके रणदीप को हरियाणा की कमान देना ज्यादा ठीक रहेगा। वैसे भी रणदीप जाट समुदाय से होने की वजह से कांग्रेस के जाट कार्ड को बखूबी भुनाएंगे। कांग्रेस अच्छी तरह समझ चुकी है कि हरियाणा को किसी जाट मुख्यमंत्री के हवाले करना ज्यादा सेफ है बनिस्बत वह किसी कुलदीप विश्नोई पर यकीन करे।

बहरहाल, रणदीप को जींद से प्रत्याशी बनाने का सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि सुरजेवाला पहले ही कैथल सीट से विधायक हैं। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस हाईकमान के दख़ल के बाद यह फ़ैसला लिया गया है और हरियाणा की राजनीति में इसके बड़े राजनीतिक मतलब हैं। जींद में 28 जनवरी को मतदान होगा और 31 जनवरी को नतीजे आएँगे। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के विधायक हरिचंद मिड्ढा के निधन की वजह से यहाँ उप-चुनाव हो रहा है।

सोच समझकर नाम किया आगे

विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही सुरजेवाला को मैदान में उतारने को लेकर तरह-तरह की चर्चाएँ हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, कांग्रेस राज्य में नेताओं की गुटबाजी से बहुत परेशान है। हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुटों के बीच कई बार लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। जाट और ग़ैर-जाट नेताओं की इस लड़ाई में कांग्रेस हाईकमान को ऐसा नेता चाहिए जो दोनों समुदायों को साध सके।

अगर सुरजेवाला इस उपचुनाव में जीत जाते हैं तो पार्टी को 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा भी मिल सकता है। इसलिए बहुत सोच-समझकर ही पार्टी ने सुरजेवाला का नाम आगे किया है।

लगाया पूरा जोर, जुटे दिग्गज

कांग्रेस किसी भी हालत में इस चुनाव को नहीं हारना चाहती, इसलिए रणदीप के नामांकन में हुड्डा, तंवर से लेकर तमाम बड़े नेता पहुँचे और एकजुटता का दावा किया। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर रही थी। सुरजेवाला कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख होने के कारण जाने-पहचाने चेहरे हैं और इस इलाके में जाट मतदाताओं के साथ-साथ अन्य वर्ग के मतदाताओं, विशेषकर युवाओं में वह काफ़ी लोकप्रिय हैं।

लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे इस उपचुनाव को हरियाणा की सियासत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस को अगर इस सीट पर जीत मिलती है तो इसका मतलब यह होगा कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस मुख्य मुक़ाबले में लौट रही है।

जींद की जनता के अलावा राज्य की जनता को भी इस बार जींद की धरती पर एक अनोखा सियासी घमासान युद्ध देखने को मिलेगा। आगामी 31 जनवरी को चुनाव परिणाम घोषित होते ही प्रदेश में अलग तरह का राजनैतिक माहौल देखने को मिल सकता है।

हरियाणा का 'दिल' व राजनीति का 'ट्रेंड सेटर' कहे जाने वाले जींद की धरती पर होने वाले इस उपचुनाव को लोकसभा के आम चुनावों से पहले जनता के मूड को भांपने का 'लिटमिस टेस्ट' माना जा रहा है । प्रदेश के पांच शहरों के मेयर पद के चुनावों में जीत के झंडे गाड़ देने के बाद उत्साहित बीजेपी आलाकमान ने शहरी व ग्रामीण मतदाताओं वाले जींद विधान सभा क्षेत्र का उपचुनाव कराने का रिस्क लेने में जरा भी देर नहीं की । इससे पहले बीजेपी नेता पांच महीने से रिक्त पड़ी इस सीट पर उप चुनाव कराने में हिचक रहे थे , लेकिन शहरी इलाकों में कमल खिलते ही बीजेपी नेताओं की बांछे खिल गईं और उन्होंने आनन-फानन में चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने की हरी झंडी दिखा दी । बीजेपी के लिए इस उप चुनाव में उतरने का इससे सुनहरी कोई और मौका हो भी नहीं सकता था , जबकि राज्य का मुख्य विपक्षी दल 'इंडियन नेशनल लोकदल' हाल ही में दोफाड़ हो चुका है और कांग्रेस भी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमों में बंटी हुई है और आपसी जूतमपैजार में लस्त-पस्त हो कर निराशा के झंझावत में फंसी पड़ी है ।

अंदर की बात...कैसे रणदीप का नाम सामने आया

असल में जींद उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी तय करने के लिए बुधवार को कांग्रेस के 15 गुरुदवारा रकाबगंज रोड स्थित वार रूम में पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में दो बैठक हुईं। पहली बैठक सुबह 10.30 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस के रणनीतिकारों को पता चला कि भाजपा ने कृष्ण मिड्ढा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। इस बैठक में कांग्रेस नेता अपना उम्मीदवार गैर जाट चुनने के लिए एकत्र हुए थे, लेकिन कृष्ण मिड्ढा का नाम आते ही पार्टी नेताओं के बीच मजबूत जाट उम्मीदवार ढूंढने की सैद्धांतिक सहमति बन गई थी। इसके बाद बैठक शाम साढ़े सात बजे तक टल गई।

इस बीच, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा एंव कुलदीप बिश्नोई के बीच राजनीतिक खिचड़ी पकी कि कलायत के निर्दलीय उम्मीदवार जयप्रकाश के बेटे विकास सहारण को उम्मीदवार बनाया जाए।

हुड्डा ने इसके लिए जयप्रकाश से बात भी कर ली थी। शाम साढ़े सात बजे जब बैठक शुरू हुई तो हुड्डा और कुलदीप बिश्नाई ने एक-एक करके जयप्रकाश का नाम आगे बढ़ा दिया । यह बात प्रदेशाध्यक्ष डॉ.अशोक तंवर को अच्छी नहीं लगी, उन्हें लगा किये पुराने नेता होने के बावजूद पार्टी हित की नहीं सोच रहे हैं। चार साल पहले जिस नेता ने कांग्रेस के अधिकृत नेता को हराया, उसे पार्टी राज्य में मजबूत स्थिति होने के बाद उपचुनाव लड़ने का न्यौता दे रही है। इससे पार्टी कॉडर के कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा।

डॉ. अशोक तंवर ने बैठक के दौरान जयप्रकाश के नाम पर अपना विरोध जताया और अब उनकी नजर रणदीप सुरजेवाला पर टिकी थीं। मगर जब पर्यवेक्षक ने बैठक में उपस्थित सभी नेताओं (तंवर को छोड़कर) ने बंद कमरे में अलग-अलग मिलकर भी जयप्रकाश के बेटे का नाम जीतने वाले प्रत्याशी के रूप में लिया तो पर्यवेक्षक ने डॉ. तंवर को भी* *विकास सहारण के नाम पर मना लिया।

बैठक से बाहर आकर रात्रि 8.45 बजे पर्यवेक्षक केसी वेणूगोपाल ने मीडिया को साफ कर दिया कि जींद उपचुनाव के लिए सर्वसम्मति से एक नाम तय कर लिया गया है। पार्टी हाईकमान की मंजूरी के बाद इसकी घोषणा करेंगे।

बस फिर क्या था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी सहित अन्य नेता खुशी-खुशी अपने गतंव्य की ओर प्रस्थान कर गए। हुड्डा ने तो अपने निवास पर पहुंचने पर वहां पहले से मौजूद कांग्रेस की टिकट मांग रहे कर्मवीर सैनी को साफ कर दिया कि पार्टी हाईकमान वहां जाट को लड़ाना चाहता है और विकास सहारण पर सभी ने सहमति जता दी है।

सैनी यह सुनकर वहां से निकले तो हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र भी निकल गए। मगर प्रदेशाध्यक्ष डॉ.अशोक तंवर ने अपने कार्यालय जाकर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सारी वस्तुस्थिति बताई और जाट उम्मीदवार पर तो सहमति जताई मगर जयप्रकाश के बेटे को टिकट का विरोध नीतिगत रूप में किया। राहुल गांधी को यह बात समझ आ गई। बस फिर क्या था।

राज्यसभा में सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण का बिल मंजूर होते ही राहुल गांधी ने तंवर को अपने पास बुलाया।

बताया जाता है कि उस समय करीब 10 बजकर 20 मिनट हुए थे। राहुल के तुगलक लेन स्थित निवास पर तंवर के साथ पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी थे। जब जाट उम्मीदवार के रूप में विकास सहारण का नाम राहुल के सामने लिया गया तो राहुल गांधी ने रणदीप सुरजेवाला को इशारा कर पूछा, वाई नॉट यू (तुम क्यों नहीं) ?

राहुल के इशारे पर रणदीप मुस्कुराए तो राहुल यह कहकर चले गए, डिक्लेयर रणदीप एज कांग्रेस कंडीडेट।

यह सारा वाक्या सिर्फ दो मिनट का था, राहुल से इशारा मिलते ही पर्यवेक्षक ने कांग्रेस महासचिव मुकल वासनिक से रणदीप के नाम का लेटर टाइप कराया और प्रेस को जारी करवा दिया। डॉ.तंवर तब भी सोए नहीं, वह फिर अपने कार्यालय गए और वहां से रणदीप सुरजेवाला का टिकट बनाकर खुद सुरजेवाला को उनके निवास पर देने गए।

अब समय ही बताएगा कि कांग्रेस द्वारा खेला गया मास्टर स्ट्रॉक कितना कामयाब हो पाता हैं। एक बात तो पक्की है, जो भी पार्टी यह चुनाव जीतेगी, आगे आने वाले चुनाव में उसका असर होना लाजमी है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06